(b) if so, the action taken thereon, and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Yes, Sir. The representation received very recently has been forwarded to the Andaman & Nicobar

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु निधियां

503. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं जिनकी मरम्मत के लिए निधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रही हैं परन्तु सरकार धन के अभाव के कारण यह धनराशि उपलब्ध नहीं करवा पा रही है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 21 तथा उत्तर प्रदेश और जयपुर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 (आगरा-भरतपुर-जयपुर-रतनगढ़-बीकानेर) की मरम्मत करने के लिए सरकार ने कितनी-कितनी राशि प्रदान की है; और

(ग) यह धनराशि किस-किस तारीख को प्रदान की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) केन्द्र सरकार राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए मानदंडों के आधार पर निधियां आबंटित करती है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। निधियों के अभाव के कारण विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता की तुलना में लगभग 50% निधियां आबंटित की गई हैं।

(ख) और (ग) रख-रखाव और मरम्मत के लिए राज्य-वार निधियां आबंटित की जाती है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों, जिनमें से रा०रा०-11 और 21 गुजरते हैं, को चालू वर्ष में अभी तक किया गया आबंटन नीचे दर्शाया गया है:

	(लाख रु०)
हिमाचल प्रदेश	1039.46
उत्तर प्रदेश	2563.40
राजस्थान	1844.08

Leasehold right of land granted by Directorate of Defence Estate

504. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the details of leasehold rights to different lands granted in the past three years to various individuals, institutions and Trade Union Organisations by the Directorate of Defence Estate, Central command;

(b) whether by grant of leasehold rights, Government have neither cared to maintain environmental aspect nor got any clearance from the concerned authority;

(c) whether law courts have granted orders of injuction and stay in such matters for various irregularities against the Central Government and others; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) The Directorate of Defence Estates, Central Command has not granted lease of Defence land in the past three years. Ministry of Defence, have, however, granted lease of Defence land in the Central Command in three cases namely—

(1) land measuring 10450 Sq.ft in Kanpur Cantt to the Indian National Defence Workers Federation (INDWF);

(2) land measuring 9548 Sq.ft to Mankameshwar Mahadev Mandir, Yammuna Bank Road, Allahabad;

(3) land measuring 25252.406 Sq.mtrs to N.V. Godgil National Society, Meerut Cantt.

(b) No irregularity in respect of environmental aspect has been committed while granting lease in these cases.

(c) and (d) In the case of lease of land to INDWF, there has been a Court Order to maintain Status-quo.